this region the contract opportunities thrown up would also increase in number, and India as an eligible country for procurement both under ordinary and the soft lending operations of the Bank would be enabled to obtain a larger number of contract awards.

Raids by Income Tax Authorities in Bombay

3947. SHRIMATI ROZA DESHPANDE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Income Tax Authorities recently raided the residences of four top executives of a leading private sector industrial group in Bombay and also the premises of two travel agencies;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) what is the value of property Government could unearth in recent raids in Bombay, Calcutta and Madras?

THE MINISTER OF STATE IN-CHARGE OF THE DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE): (a) and (b). The particulars in respect of search and seizure operations conducted in April 1976, by the Income-tax authorities in the cases of the four top executives and travel agents in Bombay are:—

Top executives		Value os assets seized
		(Rs. in lakhs)
Shri J.D. Visa, Director, Stores and Material Management, Mafatlal Services Pvt. Ltd.	Jewellery . . .	1·6
Shri B.A. Patel, Chief Cotton Purchaser, Mafatlal Group.	Cash . . .	0·1
	Jewellery . . .	2·5 (approx.)
	Fixed Deposit Receipts .	2·0
Shri S.B. Gadre, Sales Executive, Plastic Division, Hoechst Dyes and Chemicals Ltd.	Cash . . .	0·2
	Jewellery . . .	(Yet to be valued)
	Fixed Deposit receipts and pronotes . . .	0·5
Shri Hurshad Thakore, Secretary National Organic Chemicals Industries Ltd.	Fixed deposit receipts .	3·3
Travel Agents :		
Shri & Smt. Kamar Sultana Mohamed .	Cash . . .	3·9
	Jewellery . . .	0·2
Shri P.S. Jain		..
Shri Victor Rodrigues		..

Books of account/documents were also seized in this above cases.

(c) As a result of search and seizure operations conducted by the Income-tax authorities in the charges of Commissioners of Income-tax Bombay City, Calcutta and Madras (including Central charges), assets of the value of over Rs. 257.5 lakhs were seized during the period January to March 1976.

भागलपुर, बिहार में बुनकरों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण

3948. श्री रामावतार शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भागलपुर (बिहार) में बुनकरों की संख्या बहुत बड़ी है ;

(ख) क्या 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार का विचार इन बुनकरों को सहायता प्रदान करने का है ;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्होंने भागलपुर में राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिये है ;

(घ) कितने बुनकरों ने ऐसे आवेदन पत्र दिये है ; और

(ङ) अब तक ऋण प्राप्त करने वाले बुनकरों तथा उन्हें दी गयी राशि का ब्योरा क्या है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) : 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत बुनकरों को वित्तीय सहायता देने के लिये सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने विशेष योजनायें बनाई है।

(ग) से (ङ) : आंकडे सूचित करने की वर्तमान प्रणाली मे, प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्रों की संख्या अथवा सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा केवल बुनकरो को दिय गये अग्रिमों विषयक आंकडो का सकलन करने की व्यवस्था नही है।

रांची नगर का वर्ग बढाया जाना

3949. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का जनसंख्या में वृद्धि को देखते हुए रांची को बी–2 श्रेणी का नगर घोषित करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती कुमुदबेन जोशी) : मकान किराया भत्ते और प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते की मंजूरी के प्रयोजन के लिए नगरों का वर्गीकरण पिछली दशकीय जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है और अगली जनगणना तक बाद में होने वाली जनसंख्या में किसी वृद्धि को इस प्रयोजन के लिए हिसाब में नही लिया जाता। जब कि मकान किराए भत्ते के लिए नगर की जनसंख्या को हिसाब में लिया जाता है परन्तु प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते के लिए 1971 की जनगणना रिपोर्ट में बताए अनुसार, नगरीय समूह की जनसंख्या को, जहां भी यह विद्यमान हो, एक अर्हक इकाई माना जाता है। राची को, 1971 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार इसकी 1,75,934 की जनसंख्या के आधार पर मकान किराया भत्ते की मंजूरी के लिए पहले ही से श्रेणी 'ग' नगर में वर्गीकृत किया हुआ है। 1971 की जनगणना रिपोर्ट में रांची नगरीय समूह की जनसंख्या 2,55,551 दिखायी गई है जो कि प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते की मंजूरी के लिए किसी स्थान को ख–2 म वर्गीकृत करने के लिए कम से कम 4 लाख की आवश्यक अर्हक जनसंख्या से काफी कम है।

Import of raw materials by Coca Cola Export Corporation

3950 SHRI NANUBHAI N. PATEL: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government have ensured that the raw materials imported by Coca Cola Export Corporation against replenishment licences for the export of Coca Cola concentrate are used for export purposes as per conditions of the licence; and

(b) if so, the reasons for the steep fall in exports by Coca Cola Export Corporation?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the table of the House.